पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 17, अंक 3/2016

नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उपयोगिता शुल्क देना आवश्यक !

'नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उपयोगिता शुल्क देना जरूरी है और यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। टैक्स प्राप्त होने पर ही स्थानीय सरकार अच्छी सेवाएं देने में सक्षम हो सकती है।'

'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा 14 सितम्बर 2016 को जयपुर में आयोजित चतुर्थ महापौर सम्मेलन में उक्त विचार व्यक्त करते हुए राजस्थान योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. वी.एस. व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्थानीय निकायों को अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए अलग-अलग तरह के करों की संभावना तलाशनी चाहिए, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।

उक्त कार्यक्रम 'कट्स' द्वारा 'राजस्थान सिटी मेयर लर्निंग प्लेटफॉर्म' परियोजना के अन्तर्गत 'दि एशिया फाउण्डेशन' के सहयोग एवं स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में बीकानेर महापौर श्रीनारायण चौपड़ा ने कहा कि दूसरे राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा किए जा रहे सर्वश्रेष्ठ कार्यों को राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह की कार्यशालाओं में अधिक से अधिक महापौरों को भाग लेना चाहिए। भरतपुर के महापौर शिव सिंह भौंट ने कहा कि शहरी विकास के लिए महापौरों को अधिक सशक्त बनाना चाहिए।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में 'जनवाणी' संस्था पुणे की उप निदेशक सरोज बडगुजर ने पुणे में किए जा रहे कचरा प्रबंधन की तकनीक पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि पुणे में किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन एवं निस्तारण किया जा रहा है।

'जनाग्रह' संस्था बैंगलोर के परियोजना प्रबन्धक सुनील नायर ने बताया कि बैंगलोर में कचरा प्रबंधन डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। मोबाईल एप 'आई चैंज माई सिटी' पर नागरिक अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड कार्यकारी अभियंता डी. सुधाकर ने कचरा प्रबंधन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि हैदराबाद में रात्रीकालीन सफाई व रसोई के कचरे का अलग से प्रबंधन किया जा रहा है तथा राजस्व बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीके से कर लिए जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ठोस कचरा प्रबंधन नियम में संशोधन एवं स्वच्छ भारत मिशन के कुछ तकनीकी पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' ने केरल में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने राजस्थान सरकार को सिफारिश की है कि राजस्व बढ़ाने, वार्ड कमेटियों का गठन करने और ठोस कचरा प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है।

परियोजना समन्वयक अमर दीप सिंह ने सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत की जा रही गतिविधियों एवं मुख्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उक्त मेयर्स प्लेटफॉर्म को संस्थागत किए जाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में विभिन्न महापौर, उपमहापौर, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, पार्षद तथा स्वयंसेवी संस्थाओं व मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अंक में...

- घटिया सामग्री पर करोड़ों के बिल पास 3
- देश में पहली बार बनेगा इंटेग्रिटी इंडेक्स 5
- पांच साल में बढ़ गया 95 फीसदी भ्रष्टाचार ... 6
- परंपरा से हटकर हो विकास की नीति 7
- कहां से लाएंगे पीने का पानी ? 9

जैविक खेती के बारे में किसानों ने ली जानकारी

किसानों को फिर से जैविक खेती को अपनाना होगा। रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से फसलों को बचाना आवश्यक है। रासायनिक खेती से हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के साथ जहर पहुंच रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है।

रामकृष्ण शिक्षण संस्था, कोटा द्वारा आयोजित कार्यशाला में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक (प्रसार) आई.एन.गुप्ता ने किसान प्रतिनिधियों को रासायनिक खाद व कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए उक्त विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला का आयोजन 'कट्स' इंटरनेशनल एवं स्वीडन की संस्था 'एसएसएनसी' के सहयोग से प्रो–ऑर्गेनिक परियोजना के तहत किया गया। कार्यशाला में पर्यावरणविद् डॉ.एल.के. दाधीच ने रासायनिक खेती से जमीन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. मुकेश गोयल ने जैविक खाद के बारे में किसानों को विस्तार से बताया। 'कट्स' के अधिकारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने परियोजना की जानकारी दी व राजदीप पारीक ने केंचुआ खाद बनाने की तकनीक बताई। कार्यक्रम का संचालन रामकृष्ण शिक्षण संस्था के सचिव युधिष्ठर चानसी ने किया।

किसानों ने जाने जैविक खेती के फायदे

'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ की ओर से स्थानीय किसान भवन में जिला स्तरीय कृषक आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई। केन्द्र समन्वयक गौहर महमूद ने जैविक खेती से किसानों को होने वाले लाभों से परिचित कराते हुए बताया कि 'कट्स' द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एसएसएनसी स्वीडन के सहयोग से प्रो–आर्गेनिक परियोजना चलाई जा रही है।

कार्यशाला में ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र के कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. ओ.पी. शर्मा ने जैव तकनीक के द्वारा कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि किसान फिर से जैविक खेती अपनाएं। राजस्थान स्टेट बीज निगम लि. के संयंत्र प्रबंधक डॉ. राजाराम सुखवाल ने जैविक प्रमाणीकरण और विपणन की विधियों की जानकारी दी। जयपुर स्थित कट्स–कार्ट के डिप्टी हेड दीपक सक्सेना ने कहा कि प्रदेश के छह जिलों में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना चल रही है।

परियोजना अधिकारी राजदीप पारीक ने किसानों को जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने की विधि बताकर किसानों को अपने घर में ही खाद व कीटनाशक तैयार करने को प्रेरित किया। किसानों को जयसिंहपुरा जैविक कृषि फार्म का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया।

बैंक जमाकर्ताओं को जागरूक व शिक्षित करना आवश्यक!

'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से संचालित बैंक उपभोक्ताओं को जागरूक एवं शिक्षित करने की योजना के तहत चित्तौड़गढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने जमाकर्ताओं को सुरक्षित जमा के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जन–धन योजना के खाता धारकों व स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की आवश्यकता जताई।

कार्यशाला में 'कट्स–कार्ट' जयपुर के डिप्टी हेड दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संसद में 2013 में दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न बैंकों में बिना दावों के खातों में जमा कुल राशि 3652 करोड़ रुपए है। इन खातों में 10 सालों से कोई लेन–देन नहीं हो रहा। दिशा ट्रस्ट जयपुर के चीफ काउंसलर मुनीष पी. कोठारी ने उद्देश्य प्राप्ति के लिए बैंकों को भी अपने ग्राहकों को फायदे तथा जोखिम के बारे में जानकारी देने की सलाह दी।

कार्यक्रम में नाबार्ड डी.डी.एम., सचिन बाडेटिया, अग्रणी जिला प्रबंधक आर.पी. शर्मा व विभिन्न बैंकों के विषय विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों का संचालन किया और जमाकर्ताओं के अधिकारों के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ के समन्वयक गौहर महमूद ने सभी भागीदारों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मदनगिरी गोस्वामी ने किया।

लाखों क्विंटल अनाज बर्बाद

यह भारत देश के लिए त्रासदी से कम नहीं है कि बीते पांच सालों के दौरान पांच लाख क्विंटल से ज्यादा का गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ गया। इस बात का खुलासा आरटीआई के तहत बुंदेलखंड के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित द्वारा मांगी गई एक सूचना से हुआ है।

यह कैसी विडंबना है कि देश महंगाई से जूझ रहा है, खाने-पीने की सामान्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं वहीं खाद्य निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 53 हजार 143 मीट्रिक टन अनाज इन गोदामों में सड़ कर बर्बाद हो गया। दीक्षित कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को खंगालना होगा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में अन्न बर्बाद हो रहा है। *(रा.-प., 20.08.16)*

केन्द्र से मिला पैसा नहीं हुआ खर्च

प्रदेश में सरकारी विभागों द्वारा समय पर फैसला नहीं लेने से पिछले वर्ष केन्द्रीय योजनाओं के लिए मिले 244 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा।

इस पैसे का उपयोग खेती के लिए सब्सिडी, नई सड़कें बनाने, पेयजल योजना व मजदूरों का बीमा जैसे कामों में होना था। पैसा इस लिए खर्च नहीं हुआ क्योंकि अधिकारियों ने समय पर प्लानिंग ही नहीं की। कई विभागों में पैसा खर्च करने के लिए स्टाफ ही नहीं था तो कहीं समय पर टेंडर जारी नहीं होने के कारण पैसा समय पर खर्च नहीं किया जा सका। *(दै.भा., 07.09.16)*

आटा मिल में मिला गरीबों का गेहूं

चित्तौड़गढ़ जिले में भारतीय खाद्य निगम से राशन डीलरों को वितरित होने वाला अस्सी टन गेहूं आटा मिल व एक गोदाम से जब्त किया गया। स्थानीय पुलिस ने गरीबों को बांटे जाने वाले गेहूं की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर मनीष एंटरप्राईजेज के गोदाम और गोपाल ट्रेडर्स नामक आटा मिल पर छापा मारा।

पुलिस द्वारा मनीष एंटरप्राईजेज से गेहूं से भरे करीब 1000 कट्टे व गोपाल ट्रेडर्स से 300 कट्टे जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से राशन के गेहूं की कालाबाजारी की सूचनाएं मिल रही थीं। बिना मिलीभगत के यह नहीं हो सकता। *(दै.न., 29.07.16)*

घटिया सामग्री पर करोड़ों के बिल पास

-जलदाय विभाग ने एसपीएमएल कंपनी को घटिया सामग्री लगाने और देरी से काम करने पर पिछले छह माह में पेनल्टी लगाने के 18 से ज्यादा नोटिस दिए थे। इसके बाद भी विभाग के अधिकारियों ने फरवरी से जुलाई माह तक 58.91 करोड़ रुपए के बिलों का अवैध रूप से भुगतान कर दिया। इस दौरान कंपनी ने 60 करोड़ 85 लाख रुपए के बिल जलदाय विभाग में पास करने के लिए लगाए थे।

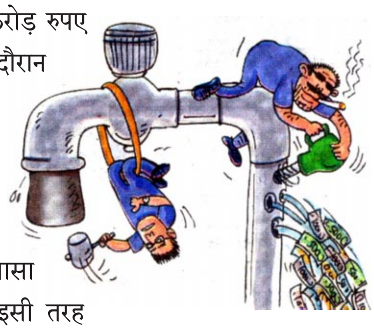

अधिकारियों की मिलीभगत होने से कंपनी पर लगाई गई 2 करोड़ 88 लाख रुपए की पैनल्टी ही नहीं काटी और भुगतान कर दिया गया। यह खुलासा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चार्जशीट में हुआ है। इसी तरह सामने आया है कि अन्य कई परियोजनाओं में भी कंपनी को करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। *(दै.भा., 18.09.16)*

नियम विरुद्ध एनीकटों का निर्माण

प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने की कवायद एवं बरसात के पानी का संग्रहण करने के लिए प्रदेश में नियमों को ताक में रखकर एनीकटों का निर्माण कर दिया गया। इससे राजकोष को कराड़ों रुपए का चूना लगा है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आया है कि सक्षम अधिकारी के अनुमोदित स्थानों के अलावा भी अधिकारियों ने तथ्यों को छुपाते हुए एनीकटों का निर्माण कर दिया। जांच में सामने आया कि झालावाड़ के सिरपोई गांव के पास पहले से एनीकट होने के बावजूद अधिकारियों ने 60.45 लाख का भुगतान कर दूसरे एनीकट बना दिए। यही हाल डूंगरपुर जिले में है जहां 19.60 करोड़ रुपए के कार्य मनमाने तरीके से आवंटित कर दिए गए। जबकि वहां भी पहले से एनीकट बने हुए थे। *(दै.न., 25.09.16)*

उपलब्ध पैसा भी समय पर खर्च नहीं

ग्रामसभाओं में खानापूर्ति के चलते योजनाओं के वास्तविक परिणाम हासिल नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामसभाओं में इससे जरूरी प्रस्ताव समय पर स्वीकृत नहीं हो पाते। इससे उपलब्ध पैसा भी समय पर खर्च नहीं हो पाता। इसी वजह से पिछली साल 27 जिलों की 111 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध राशि का एक रुपया भी खर्च नहीं हो पाया।

राज्य वित्त आयोग ने भी निधियों के समय पर उपयोग नहीं करने को गंभीर माना है। अब आयोग की सिफारिशों के बाद पंचायतीराज ग्रामसभाओं का नए सिरे से मजबूत रोडमैप बनाएगा। इसके अलावा खर्च व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। *(दै.न., 09.09.16)*

छह माह भी नहीं चली सड़क

जयपुर से किशनगढ़ तक छह लेन नेशनल हाईवे निर्माण में भारी कमियां सामने आई है। 90 किलोमीटर लम्बी यह सड़क 150 करोड़ रुपए खर्च कर नई बनाई गई है। लेकिन छह माह में ही एक तरफ से पूरी टूट गई। इसके बावजूद टोल वसूली जारी है।

छह लेन के मामले में देश के समक्ष नजीर पेश करने वाली यह सड़क गांव की सड़कों से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई। सड़क जगह-जगह से टूट गई है। एन.एन गिरी, परियोजना निदेशक एनएचएआई का कहना है कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी तो हुई है। जिस कंपनी ने गड़बड़ी की, उसे पांच साल तक सड़क का रखरखाव करना है। उसे सड़क दुबारा बनानी ही होगी। *(रा.प., 09.08.10)*

लाखों लोग ले रहे महंगा इलाज

सरकारी स्तर पर सस्ती और निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं के तमाम दावों के बावजूद राजधानी जयपुर में अल्प और मध्यम आय वर्ग वाले करीब 20 लाख लोग निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में महंगा उपचार ले रहे हैं।

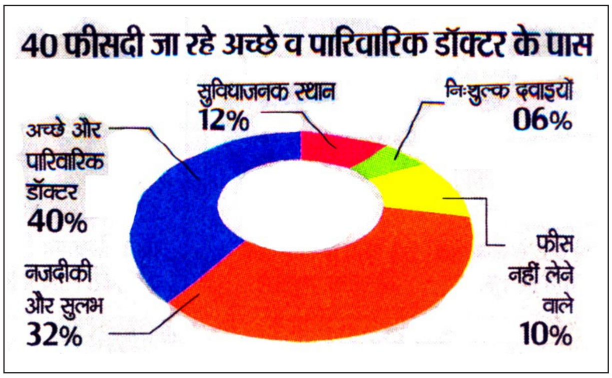

'कट्स' इंटरनेशनल की ओर से ऑक्सफॉम इंडिया के सहयोग से जयपुर शहर में किए एक पायलट सर्वे के अनुसार कम आय वाले आधे लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। न्यूनतम आय वाले परिवारों का स्वास्थ्य पर मासिक खर्च कुल आय का 11 फीसदी तक हो रहा है। जबकि, मध्यम आय वर्ग में यह प्रतिशत 5.7 फीसदी व उच्च आय वर्ग में 3.65 फीसदी रहा। सर्वे में यह उभर कर आया है कि आधी आबादी पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव सहित डॉक्टर्स की फीस, जांच शुल्क, महंगी दवाई व चिकित्सा सेवा की अन्य सुविधाओं का भारी खर्चा उठा रही है। खासतौर पर सामने आया है कि न्यून आय वाले सेहत जैसी मुख्य सेवा पर अन्य से दोगुना खर्च कर रहे हैं।

(रा.प., 10.07.16)

उजागर हुआ 40 करोड़ का घोटाला

जलदाय विभाग की ओर से प्रदेश के 6800 ट्यूबवैलों में लगाए गए सबमर्सिबल पंपों और उनके साथ डाली गई बिजली केबलों में 40 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और जलदाय विभाग की क्वालिटी कंट्रोल विंग ने इस घोटाले को उजागर किया है।

जांच में सामने आया है कि इंजीनियरों ने ठेकेदार फर्म से मिलीभगत कर न केवल कई जगह घटिया सबमर्सिबल पंप डाले, बल्कि तय मापदंडों की मोटाई वाली केबल की जगह कम मोटाई वाली और सस्ती केबल डालकर भुगतान उठा लिया। अधिकांश जगह पर केबल भी पूरी नहीं डाली गई जबकि भुगतान 400 मीटर तक का उठाया गया है। मामले में एक्सईएन से लेकर डिविजन अकाउंटेंट व स्टोर कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ रही है।

(दै.भा., 26.09.16)

सरकारी दवाइयों के सैंपल फेल

मरीज पूरे विश्वास के साथ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलने वाली दवाओं का सेवन कर उम्मीद करता है कि जल्द ही बीमारी से निजात मिलेगी। मगर हकीकत कुछ और है।

राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली दवाईयों के गत दो वर्षों में 288 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें मधुमेह, एंटीबायोटिक, विटामिन आदि की दवाईयां शामिल है। गंभीर बात यह है कि ज्यादातर दवाइयों की जांच में सॉल्ट की मात्रा शून्य मिली। नकली व अधोमानक दवाईयों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को दी जाने वाली पेरासिटामॉल टेबलेट व सिरप भी अधोमानक थी। जाहिर है कि इससे उनके मर्ज में भी यह दवाएं बेअसर रही होंगी।

(रा.प., 07.08.16)

उज्वला योजना में विधायकों के नाम

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी सूची में ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत व पूर्व विधायक देवी सिंह भूतड़ा सहित कई सक्षम लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला माना गया है। सूची में ऐसे कई नामों के आने से बीपीएल परिवारों के चयन में गड़बड़ी साफ नजर आ रही है।

उज्ज्वला योजना के लिए जारी सूची 2011 के आर्थिक सर्वे के आधार पर बनी है। जरूरी यह है कि गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्वला योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद को मिल सके।

(रा.प., 10.07.16)

परियोजनाएं लटकी, लागत बढ़ी

देश के आर्थिक विकास की गति को मजबूती देने के लिए केन्द्र सरकार बड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन देरी के चलते एक हजार करोड़ या इससे भी अधिक की करीब 101 बड़ी परियोजनाओं की लागत 1.29 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।

यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि अन्य परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हुआ तो लागत और भी बढ़ सकती है।

सांख्यिकी मंत्रालय ने अप्रेल 2016 में पावर, रेल्वे और सड़क जैसे कई सेक्टर्स के एक हजार करोड़ या इससे ज्यादा के 286 आधारभूत ढांचों से संबंधित बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि देरी के चलते ज्यादातर परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है।

(रा.प., 01.08.16)

करोड़ों के कृषि उत्पाद हर साल बर्बाद

देश में हर साल जितने रुपए की सब्जियां खराब होती है, उतने में तीन साल का कृषि बजट बनाया जा सकता है। केन्द्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार हर साल 92 हजार 651 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद खराब हो जाते हैं। जबकि 2015-16 का कृषि बजट 35 हजार 984 करोड़ रुपए है। यह खराब कृषि उत्पादों की लागत से करीब तीन गुणा ज्यादा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इस साल कृषि बजट में पिछले साल के मुकाबले 44 फीसदी की बढ़ोतरी की है। देश में फलों-सब्जियों और अनाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भंडारण की कमी है। लगभग 60 फीसदी चीजें भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है।

(रा.प., 12.08.16)

जलदाय विभाग में घूस की महिमा

जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार के दौरान ही घूसखोरी का दौर शुरू हो चुका था। वर्ष 2013 में विभाग का बजट 2500 करोड़ रुपए था, जबकि अफसरों ने 10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पास कर दिए। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट भाजपा सरकार में भी स्वीकृत हुए हैं। कंपनियों से मोटी रिश्वत लेने के लिए बिना बजट प्रोजेक्ट पास किए थे।

ऐसे में जिस कंपनी से मोटी रकम मिलती, विभाग के अधिकारी उसी के बिलों को पिछले ढाई साल से स्वीकृत कर भुगतान कर रहे थे। यह खुलासा रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा व एडीशनल चीफ सुबोध जैन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की पूछताछ में किया है। वे कंपनियों से रिश्वत नहीं मांगते थे, कंपनी वाले खुद ही देकर जाते थे।

बजट नहीं होने से कंपनियों ने बैंकों से लोन लेकर काम तो कर दिया, लेकिन बिल पास करवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। कंपनी के अधिकारियों की सचिवालय तक अच्छी पकड़ थी। दस हजार में से अकेले एसपीएमएल कंपनी को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर मिले थे। *(दै.भा., 02.08.16)*

कालाधन रखने वालों पर मुसीबत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कालाधन रखने वालों को फिर चेताया है। उन्होंने कहा है कि अघोषित संपत्ति रखने वाले 30 सितंबर तक उसका खुलासा कर पाक-साफ हो लें और चैन की नींद सोएं। अन्यथा इसके बाद उन्हें जेल सहित अन्य कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को घोषित संपत्ति पर 45 फीसदी टैक्स व जुर्माना चुकाना होगा। इस योजना का फायदा नहीं लेने वालों को सख्त मुसीबतों का सामना करना होगा।

(दै.भा. एवं दै.न., 24.07.16)

भ्रष्टाचार का खुलासा होने का डर

ऑडिट में भ्रष्टाचार का खुलासा होने के डर से प्रदेश के 88 सरकारी विभाग ऑडिट दलों को सात साल से सही जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। मुख्य सचिव स्तर की आपत्ति के छह महिने के बाद भी विभागों के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। विभाग सूचना छिपाने की बार-बार कोशिश करते हैं।

वित्त विभाग भी विभागों के इस रवैये पर फरवरी माह में चेतावनी जारी कर चुका है। अब विधानसभा की जनलेखा समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है। इससे विभाग अपने कार्मिकों पर सही तथ्य जारी करने का दबाव बनाने लगे हैं। यदि कोई कार्मिक या अफसर तथ्यों को छिपाने का दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलेगा।

(दै.न., 01.09.16)

सरकार बचा रही भ्रष्ट कर्मियों को

हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद राज्य सरकार घूसखोर, पद का दुरुपयोग करने व अवैध राशि वसूलने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बचा रही है। प्रदेश में 195 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के अभाव में लम्बित हैं। इनमें से राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 31 प्रकरणों को कार्मिक विभाग व 164 प्रकरणों को विभिन्न विभागाध्यक्ष लेकर बैठे हुए हैं।

सर्वाधिक कार्मिक, पंचायत व राजस्व विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों का बचाव कर अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है। जबकि न्यायालय के आदेशानुसार जनवरी 2016 तक एसीबी में दर्ज प्रकरणों पर 90 दिन के अन्दर निस्तारण करना था। लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

(डे.न्यू., 25.09.16)

कालाधन के आंकड़े साझा करे

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कालेधन पर बने विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया है कि वह मुद्रा विनिमय, देश से बाहर पड़ी निर्यात की आमदनी तथा आयात के अग्रिम भुगतान के आंकड़े राजस्व विभाग के साथ ऑनलाइन साझा करने के लिए प्रणाली विकसित करें।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि एसआईटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम. बी. शाह ने आरबीआई को भेजे एक पत्र में कहा है कि केन्द्रीय बैंक राजस्व विभाग के साथ विचार विमर्श कर एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिस पर विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी लेनदेन, निर्यात के मद में हुए देश से बाहर पड़े भुगतान तथा आयात के मद में किए गए अग्रिम भुगतान के आंकड़े ऑनलाइन साझा किए जा सकें।

(दै.न., 06.09.16)

बड़े घपलों की रिपोर्ट देंगे बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जानकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को देनी होगी। सीबीआई को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के.वी. चौधरी ने बताया कि बैंकों से धोखाधड़ी मामलों की शिकायत हासिल करने के लिए यह केन्द्रीयकृत ऐजेंसी के रूप में काम करेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जबकि रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंकों के पास सीबीआई में शिकायत के लिए 'फोकल पाइंट' नहीं है।

(न.नु., 09.08.16)

देश में पहली बार बनेगा इंटेग्रिटी इंडेक्स

सरकारी एजेंसियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने और उस पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने देश में पहला इंटेग्रिटी इंडेक्स (समग्रता सूचकांक) तैयार करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी ऐजेंसियों के भ्रष्टाचार की रेटिंग तय होगी। इससे सीवीसी यह बता सकेगा कि कौनसा सरकारी विभाग कितना भ्रष्ट है।

इंटेग्रिटी इंडेक्स तैयार करने में सरकारी ऐजेंसियों के स्टेक होल्डर्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सीवीसी रिसर्च बेस्ड अप्रोच को अपनाने पर बल देगी। इसमें शिक्षण संस्थानों की भी मदद ली जाएगी।

(रा.प., 31.07.16)

पांच साल में बढ़ गया 95 फीसदी भ्रष्टाचार

एक अनुमान के अनुसार भारत में शहरी परिवार हर साल 2.12 लाख करोड़ रुपए घूस में दे देते हैं। ग्रामीण परिवार भी घूस देने में कम नहीं हैं। वह साल में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए घूस देते हैं। बीते पांच साल में भ्रष्टाचार 95 फीसदी बढ़ गया जबकि सजा 5 फीसदी को भी नहीं हुई। सीबीआई ने पिछले पांच साल में 3296 केस दर्ज किए। सिर्फ 169 आरोपियों को ही सजा हो पाई, यानी सिर्फ पांच प्रतिशत।

वर्ष 2009 में गजेटेड स्तर के 1164 अफसर पकड़े गए थे। जबकि 2013 में यह आंकड़ा बढ़कर 2274 हो गया। यानी करीब दोगुना। ये वे मामले हैं जिनमें राज्यों की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। हमारे यहां 62 प्रतिशत भारतीयों को कभी न कभी घूस देनी पड़ी है। दुनिया में भ्रष्टाचार की औसत दर से दोगुना हमारे यहां भ्रष्टाचार है।

सरकारी दफ्तर जाने वाले हर दूसरे व्यक्ति को घूस देनी पड़ती हैं। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और अर्थशास्त्री अरुण कुमार के मुताबिक देश की व्हाइट इकोनॉमी फिलहाल 150 लाख करोड़ रुपए की है। जबकि इसके समानान्तर 90 लाख करोड़ रुपए की ब्लेक इकोनॉमी चल रही है। *(दै.भा., 31.07.16)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बारां	शैतान सिंह	ग्राम सेवक, अटरू व दड़ा ग्राम पंचायत	49,000	रा.प., 02.07.16
धौलपुर	गिरीश कुमार गुप्ता ईश्वरी प्रसाद शर्मा	प्रबंधक, भरतपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि., बसेड़ी ऋण निरीक्षक, भरतपुर सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	15,000	रा.प., 02.07.16
सीकर	उम्मेद सिंह दिनेश कुमार वर्मा	सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, खंडेला लिपिक, विद्युत विभाग, खंडेला	10,000	रा.प., 02.07.16
जोधपुर	मुकुल जोशी	कम्प्यूटर ऑपरेटर, होमगार्ड कार्यालय, पुलिस लाइन	5,000	दै.न., 12.07.16
चूरू	विद्याधर मेघवाल	आबकारी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक कार्यालय	9,000	रा.प., 16.07.16
चित्तौड़गढ़	शांतिलाल वैष्णव	मुख्यआरक्षी, समादेष्टा गृहरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	15,000	दै.न., 20.07.16
अलवर	नंदराम यादव	पटवारी, पैतपुर गांव हल्का	10,000	रा.प., 22.07.16
बाड़मेर	सूरजन विश्नोई	एमआईएस, नरेगा कार्यालय चौहटन पंचायत समिति	12,000	दै.भा., 04.08.16
जयपुर	रस लाल	एसएचओ, पीसीपीएनडीटी थाना	8,000	दै.भा., 14.08.16
जैसलमेर	राम दयाल	टीआरए, उपनिवेशन तहसील कार्यालय, जैसलमेर	30,000	दै.न., 17.08.16
जोधपुर	नरेन्द्र कालरा	एडिशनल चीफ इंजीनियर, राज. विद्युत प्रसारण निगम	25,000	दै.भा., 24.08.16
झुंझुनूं	सतवीर सिंह धनकड़	अधिशासी अभियंता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम	20,000	दै.भा., 24.08.16
जैसलमेर	सुरेश माथुर	अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	70,000	दै.भा. एवं दै.न., 24.08.16
अलवर	चेतराम मीणा धनीराम यादव	चेयरमैन का पीए, सरस डेयरी, अलवर सदस्य, तिजारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	45,000	रा.प. एवं दै.भा., 01.09.16
भरतपुर	जितेन्द्र यादव	सचिव, नदबई कृषि उपज मंडी, भरतपुर	30,000	रा.प. एवं दै.न., 05.09.16
जयपुर	गणेश जाट गोपाल यादव	पटवारी, सांगानेर तहसील, जयपुर प्रॉपर्टी डीलर, पटवारी का साथी, मुरलीपुरा	46,500	रा.प. एवं दै.भा., 28.09.16

निर्मल चरित्र हो पवित्र आत्मा! भ्रष्टाचार का तभी खात्मा!!

आदर्श ग्राम योजना का होगा मूल्यांकन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। इसके तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय सांसदों के गोद लिए गांवों का अब तक का मूल्यांकन करा कर जमीनी हकीकत जानना चाहता है।

केन्द्र की टीम उन गांवों का दौरा कर सांसदों द्वारा गांव में किए कार्यों की असलीयत देखकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर गांवों की रैंकिंग तय की जाएगी। पीएमओ कार्यालय का मानना है कि योजना में ज्यादातर सांसदों ने काम में दिलचस्पी नहीं ली और गोद लिए गांवों की स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है। *(रा.प., 03.07.16)*

जीएसटी विधेयक पारित

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधित विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देशभर में इसे लागू करने का आगे का रास्ता साफ हो गया है। देश के कुल 29 राज्यों में से 16 राज्यों ने अपनी विधान सभाओं में जीएसटी विधेयक पारित कर दिया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कराधान में एक बड़ा आर्थिक सुधार है, जो काफी समय से लंबित चल रहा था। इससे अब अगले साल एक अप्रेल से देशभर में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। *(दै.न., 09.09.16)*

शोध का हब बना अपना देश

भारत विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों समेत वैज्ञानिक और रिसर्च का केन्द्र बन कर उभर रहा है। देश में पिछले कुछ सालों से दुनियाभर की करीब 1000 कंपनियों ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए हैं।

इन कंपनियों में दो लाख से भी अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं। इनमें 25 फीसदी वे लोग हैं, जिन्होंने दुनियाभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद स्वदेश का रुख किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में 36 फीसदी यानी हर 10 में से 6 वैज्ञानिक भारतीय हैं। अमरीका में 38 फीसदी डॉक्टर भी भारतीय हैं। भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक सी.एन.आर. राव ने कहा है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की आवश्कता है। *(रा.प., 15.08.16)*

नजर कमजोर तो मुफ्त मिलेगा चश्मा

अगर आपकी उम्र 45 साल या इससे अधिक है और पास की नजर कमजोर है तो चिंता की जरूरत नहीं। राज्य सरकार आपको मुफ्त में चश्मा उपलब्ध कराएगी।

सरकार ने इसकी योजना बना ली है। इस प्रकार चश्मा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान होगा। करीबन 30 हजार चश्में बांटने की योजना है। इसमें बीपीएल को प्राथमिकता दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत प्रेसबायोपिक अर्थात पास की नजर कमजोर होने की बीमारी के पीड़ितों को निःशुल्क चश्में देने की योजना है। *(दै.भा., 24.07.16)*

गलती से पेंशन बंद तो दुबारा शुरू

गलत तरीके से पेंशन बंद होने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक, पटवारी व वार्ड पंच की संयुक्त टीम इसकी जांच करेगी। शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद व नगर निकाय के अधिकारियों की टीम जांच करेगी। यदि गलत तरीके से पेंशन बंद हुई है तो गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि यदि किसी की गलत तरीके से पेंशन बंद हुई है तो दुबारा शुरू की जाएगी। इसके लिए पेंशनर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए शिकायत दे सकता है। जितने महीने पेंशन बंद रही है उसका एरियर भी दिया जाएगा। *(रा.प., 09.09.16)*

परंपरा से हटकर हो विकास की नीति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग को एक विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए बुलाया और कहा कि देश के विकास की नई नीति परंपराओं से हटकर हों। यह दस्तावेज भारत के अगले 15 वर्षों के विकास का रोडमैप या रूपरेखा तैयार करने के साथ ही 21वीं सदी के आने वाले दशकों में देश के विकास में तीव्र वृद्धि की नींव रखेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय तक वृद्धि संबंधी सुधारों का समय जो पूरे विश्व का मानक था अब खत्म हो चुका है। मौजूदा युग एक ऐसा है जिसमें रूपांतरणीय बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र के पास लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाने का साहस और क्षमता है और भारत के प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण और बुद्धिमता पूर्वक इस्तेमाल इस परिवर्तन के केन्द्र में होगा। *(न.नु., 01.08.16)*

प्रदेश में शुरू होगी वृक्षकुंज योजना

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण से प्रदेश में वृक्षकुंज योजना की शुरुआत की जाएगी। द्वितीय चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगी।

इसमें करीब एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

योजना में 100 पौधे लगा कर उनकी देखभाल करने वाले को नरेगा के तहत सरकार 3800 रुपए का भुगतान करेगी। योजना को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अलावा ग्रामीण विकास और वन विभाग मिल कर चलाएंगे। वृक्षकुंज योजना में पैसा तभी मिलेगा, जब चरागाह, गोचर या अन्य सार्वजनिक जमीन पर कम से कम 100 पेड़ लगाकर उनकी देखभाल की जाएगी। *(दै.न., 09.08.16)*

जेब पर लगा बिजली बिल का करंट

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को छह साल में पांचवी बार महंगी बिजली का करंट झेलना पड़ रहा है। घरेलू बिजली में 35 पैसे से 75 पैसे व्यावसायिक श्रेणी में 95 पैसे व औद्योगिक श्रेणी में 80 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें एक सितम्बर से लागू की गई है।

इसके अलावा सभी श्रेणियों के स्थाई शुल्क में भी 20 से 30 रुपए प्रति माह बढ़ाए गए हैं। बीपीएल, कृषि व 50 यूनिट तक हर माह बिजली उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ता की जेब पर भी भार पड़ेगा। अब बीपीएल परिवारों को 25 पैसे, छोटे उपभोक्ताओं को 35 पैसे और किसानों को 25 से 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि उक्त तीनों श्रेणियों में वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी यथावत रहेगी। *(रा.प., 23.09.16)*

बिजली उत्पादन वृद्धि हुई दोगुनी

इस साल बिजली उत्पादन वृद्धि दर साढ़े नौ प्रतिशत रही है। यह पिछली संप्रग सरकार के 2004 से 2014 के कार्यकाल के दौरान रही वृद्धि दर 5.65 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है।

वर्ष 2004 से 2014 के बीच बिजली उत्पादन में वृद्धि की दर 5.65 प्रतिशत रही जो 2012-14 में 5.02 प्रतिशत, 2014-16 में 7.03 प्रतिशत और 2016 में अब तक साढ़े नौ प्रतिशत है। मात्र दो साल के भीतर ऊर्जा की कमी में 87 प्रतिशत की गिरावट आई है। पहले यह 11 करोड़ यूनिट थी जो अब घटकर 1.4 करोड़ यूनिट रह गई है। *(न.नु., 05.07.16)*

दफ्तरों में हो रही बिजली बर्बाद!

प्रदेश के सरकारी दफ्तर केन्द्र सरकार की ऊर्जा बचत मुहिम की हवा निकाल रहे हैं। एक ओर जहां 21 लाख उपभोक्ता एलईडी अभियान से जुड़कर रोजाना 40 लाख यूनिट बिजली बचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तर आज भी हजारों की तादाद में ट्यूबलाइट व सीएफएल से रोशन हो रहे हैं।

ऊर्जा बचत का काम देख रही केन्द्रीय एजेंसी के दावे के अनुसार इन दफ्तरों में एनर्जी एफिशिएंट ट्यूबलाइटें लगाने से 30 से 40 फीसदी तक बिजली खपत कम हो सकती है। ऐसी ट्यूबलाइटें लगाकर रोजाना करीब डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की बिजली बचत की जा सकती है। *(रा.प., 20.09.16)*

बढ़ेगा विंड एनर्जी का दायरा

सोलर एनर्जी के साथ ही केन्द्र सरकार राजस्थान में विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने जा रही है। राज्य के तकरीबन 12 जिलों में विंड एनर्जी के बड़े स्कोप को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इसमें खास रुचि दिखाई है। निजी डवलपर्स को विंड एनर्जी प्लांट लगाने में मदद के लिए केन्द्रीय सहायता देने के तैयार प्रावधानों का आगामी आवेदकों को लाभ मिलेगा।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के निजी डवलपर्स का रुझान बढ़ाने के लिए प्लांट से जुड़े संसाधनों में वैट और टैक्स सहित अन्य सब्सिडी देने की योजना बनाई है। *(दै.न., 29.08.16)*

मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान शुरू

प्रदेश में बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान कर छीजत के स्तर को 15 प्रतिशत तक रखने के लिए 31 दिसम्बर 2017 तक तीन चरणों में मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की समीक्षा के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निर्देशन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला प्रभार स्तरीय, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय, तथा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सभी कमेटियां अपने-अपने स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभियान से जुड़कर नीति निर्धारण, जनप्रतिनिधियों से संवाद, प्रबोधन एवं समीक्षा का कार्य करेंगी। *(दै.न., 23.09.16)*

तय किया सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

सरकार ने मार्च 2022 तक देश में एक लाख मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बिजली, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने कहा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 हजार मेगावाट से अधिक सौर विद्युत क्षमता के लक्ष्य के साथ लगभग 25 सौर पार्क और अल्ट्रामेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जानी है।

राज्यसभा में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने भी एक पूरक प्रश्न के जवाब में जानकारी दी कि सरकार का प्रयास अगले 10 साल में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर तीन गुना करने का है। देश में वर्तमान में 21 परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 5780 मेगावाट है। *(न.नु., 22.07.16)*

विद्युत सेवा सुधार की आस धूमिल

हर साल आपके बिजली बिल में करंट दौड़ा रहे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के ताजा फरमान से बिजली क्षेत्र में सेवा सुधार की आस लगाए बैठे टेक्नोक्रेट्स व आमजन को बड़ा झटका लगा है।

बिजली आपूर्ति में दिक्कतें, नए कनेक्शन में देरी, और हाईवोल्टेज से घरों में नुकसान जैसे बढ़ते मामलों के पीछे स्टाफ की कमी और तय मापदण्ड नहीं होने के अभियंताओं के तर्क को आयोग ने जायज मान लिया। लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर सख्ती की बजाय आयोग के 4 अगस्त के आदेश में महज सुझाव नजर आए हैं। बिजली मामलों के विशेषज्ञ इसको खानापूर्ति बता रहे हैं। *(रा.प., 07.08.16)*

कहां से लाएंगे पीने का पानी ?

ज्यादा जल दोहन से प्रदेश में भूमि का जल स्तर गड़बड़ा गया है। सबसे सुरक्षित हालात गंगानगर के हैं तो सबसे खराब झूंझुनूं जिले के हैं। यही हालात रहे तो कई जिलों में पीने के पानी की समस्या आ सकती है। दो दशक में भूजल दोहन कई गुणा बढ़ा है। कम व अनियमित वर्षा के कारण भी पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविधालय के भूजल विभाग के सर्वे में सामने आया है कि प्रदेश के 26 जिलों में भूजल स्तर 0.13 से 6.86 मीटर तक नीचे चला गया है। भूजल के हिसाब से राज्य 249 जोन में बंटा है। इनमें से 31 जोन सुरक्षित, 43 क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल तथा 172 डार्क जोन में हैं।

(रा.प., 26.07.16)

पीने के लिए शुद्ध पानी का टोटा

हर साल शुद्ध पेयजल को लेकर भले ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए जा रहे हों,लेकिन इसके बाद भी लोगों को गुणवत्तायुक्त पेयजल मुहैया नहीं हो पा रहा है। विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में लिए गए पानी के नमूनों की जांच में सामने आया है कि पीने का पानी जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

हाल ही अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रदेशभर में पानी के सैम्पल एकत्रित किए गए। करीब 1000 से अधिक सैम्पलों की जांच में सामने आया कि 384 सैम्पलों में पानी पीने योग्य नहीं है। इस पानी के सेवन से कई तरह की बीमारियों का जंजाल फैलता जा रहा है। जांच से यह साबित होता है कि प्रदेश के 33 जिलों में से करीब 26 जिलों में पानी पीने योग्य नहीं हैं। *(दै.न., 23.08.16)*

जल स्वावलंबन कामों की होगी जांच

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से करवाई जाएगी। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में थर्ड पार्टी की ओर से कार्यों की रेण्डम औचक जांच की जाएगी। कलेक्टर जिला स्तर पर अभियान की सप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीराम वेदिरे ने यह जानकारी देते हुए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के द्वितीय चरण में शामिल 4200 गांवों के वाटरशेड के शत प्रतिशत क्षेत्र का सर्वे सुनिश्चित करें और जिलेवार सिंचाई योजना तैयार की जाए।

(दै.न., 09.09.16)

जल संरक्षण कार्यों से सुधरे हालात

प्रदेश में चल रहे जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रथम चरण में 5 माह में 90 हजार जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहां बारिश के बाद जल भराव से वर्षा जल संरक्षित हो रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब दूसरे चरण में 3500 गांवों का चयन किया जाएगा। इसके लिए गांवों में जाकर नए जलग्रहण विकास कार्यों की कार्य योजना बनाई जा रही है। इससे कार्यों के क्रियान्वयन में सुविधा रहेगी। *(डे. न्यू., 13.07.16)*

शहरों में जल स्वावलंबन अभियान

प्रदेश के सभी 190 शहरों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जाएगा। दो चरणों में चलने वाले अभियान को 30 जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत नवंबर 2016 से होगी, जिसके निर्धारित कार्य 30 जून 2017 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

अभियान की सफलता और अड़चनों को दूर रखने के लिए सात स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों की अभियान पर पूरी नजर रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने अभियान की क्रियान्विति को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अभियान के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है। *(दै.न., 08.09.16)*

जयपुर में 11 ब्लॉक्स डार्क जोन में

जयपुर जिले में भूगर्भीय जल स्तर के हालात चिंताजनक है। जिले में भूगर्भीय जल के 13 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से सिर्फ दो ब्लॉक दूदू-चाकसू को छोड़कर अधिकांश 11 स्थानों पर हालत चिंताजनक है

प्रदेश में हो रही बरसात से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। ग्राउण्ड वाटर विभाग के मुख्य अभियंता सूरजभान सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह में प्रदेशभर में भूगर्भीय जलस्तर का अध्ययन किया जाएगा। *(दै.न., 11.09.16)*

सोलर पंप पर मिल सकेगी राहत

प्रदेश में किसानों को बिजली के बोझ से बचाने के लिए सरकार सोलर पंपों पर 85 फीसदी तक अनुदान देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग तैयार कर रहा है। अभी सरकारी स्तर पर मंजूरी मिलने की प्रक्रिया बाकी है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में यह योजना लागू हुई तो पहले उन किसानों को फायदा दिया जाएगा, जिनके तीन व चार हॉर्सपावर के कनेक्शन लंबित पड़े हैं। योजना लागू होने पर किसान को सोलर पंप खरीदने पर केवल 15 फीसदी राशि ही चुकानी पड़ेगी। इससे किसान को बिजली बिल में काफी हद तक राहत मिलेगी। *(दै.न., 28.09.16)*

बनेंगे सवा लाख जल संग्रहण स्त्रोत

राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का दूसरा चरण 16 नवम्बर से शुरू होगा। इसमें 4200 गांवों और शहरों में सवा लाख नए जल संग्रहण स्त्रोत या ढांचों का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण के सात माह में 3529 गांवों में 93 हजार 230 जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं।

यह जानकारी चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कृषि पंत भवन की बैठक में देते हुए बताया कि दूसरे चरण के बाद शेष रहे गांवों में भी जल संग्रहण ढांचे विकसित किए जाएंगे। गांवों को गोद लेने के साथ ही आम सहभागिता से श्रमदान भी कराया जाएगा। *(दै.न., 22.09.16)*

कारोबार के गुर सिखाएगी सरकार

व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राज्य सरकार बेहतर करोबार के गुर सिखाएगी। इसके लिए जिलेवार ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया गया है। सहकारिता विभाग ने जिलेवार केन्द्रीय सहायक बैंकों को राशि आवंटित की है। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

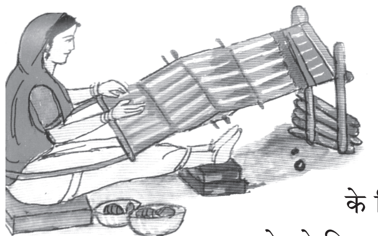

चयनित स्वयं यहायता समूह के सदस्यों की रुचि एवं आवश्यकतानुसार व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए जिला स्तर पर संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से जिला उद्योग केन्द्र रूडा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड या स्थानीय कार्यरत एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। *(दै.न., 26.09.16)*

'उज्ज्वला' योजना बनी वरदान

सालों से चूल्हे के धुएं की पीड़ा झेल रही गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना वरदान साबित हुई है। दो माह में 2.2 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में दूसरे और करीब 6.5 लाख कनेक्शन जारी कर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। योजना के तहत एक साल में 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य है। तेल मंत्रालय के मुताबिक प्रदेश में उदयपुर सबसे आगे है। इसके बाद जयपुर, टोंक व नागौर का नंबर है। आईओसीएल व राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) के कार्यकारी निदेशक सुनील माथुर ने बताया कि योजना में 2.20 लाख कनेक्शन जारी हो चुके हैं। अगले माह में आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। *(रा.प., 06.07.16)*

प्रदेश में गिरता लिंगानुपात

प्रदेश में बेटियों की कम होती संख्या अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश में 0 से 1 साल तक के बच्चों में लड़कों की तुलना में 86 हजार कम लड़कियां हैं।

इस आयु वर्ग में लड़कों की संख्या 7,22,108 है जबकि इनकी तुलना में लड़कियों की संख्या 6,35,198 है। यहां 100 लड़कियों पर लड़कों की संख्या 113.7 है। जबकि देश का कुल अनुपात 109.9 है। इस लिहाज से खराब राज्यों की सूची में राजस्थान आठवें स्थान पर है। इस मामले में देश में सबसे बेहतर स्थिति वाला राज्य मिजोरम है। यहां 100 लड़कियों पर लड़कों का अनुपात 101.1 है। जबकि 100 लड़कियों पर 128 लड़कों के साथ जम्मू कश्मीर सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है। *(रा.प., 26.09.16)*

महिलाओं के मातृत्व अवकाश बढ़े

केन्द्र सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। यह देशभर की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का ही लाभ मिलता था। कोई भी कामकाजी महिला इस सुविधा का लाभ केवल दो बच्चों के जन्म पर ही ले सकती है। तीसरी संतान की स्थिति में यह लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। *(दै.न., 11.08.16)*

प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल-विवाह

देश में सबसे अधिक बाल-विवाह राजस्थान में हुए हैं। यहां मौजूदा विवाहित लोगों में से 30 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनका विवाह बचपन में ही हो गया। हालांकि पुरुषों और महिलाओं में तुलनात्मक रूप से इस आंकड़े में भारी अंतर पाया गया। जहां विवाहित पुरुषों में 16 फीसदी विवाह बचपन में ही हो गया, वहीं विवाहित महिलाओं में 43 फीसदी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बचपन में ही ब्याह दिया गया।

यह आंकड़े राष्ट्रीय औसत जो कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी और पुरुषों के लिए 7 फीसदी है, से काफी ज्यादा है। प्रदेश में दीर्घकालीन परिवर्तन लाने के लिए कानूनों का सख्ती से लागू करना होगा। जिनमें बच्चों की उम्र के निर्धारण के लिए विवाह के पंजीकरण भी शामिल है। *(दै.न., 12.07.16)*

'यूएन वुमन' करेगा सशक्तीकरण

राज्य सरकार बजट के अभाव में महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश महिला शिक्षा के मामले में नीचे से दूसरे पायदान पर है, कन्या भ्रूण हत्या में काफी आगे, शिशु मृत्यु दर में देश में तीसरे नंबर पर है। इसलिए अब प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का बीड़ा यूएन वुमन (संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला शाखा) ने उठाया है।

यह महिला सुरक्षा, महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाने, जेंडर बजटिंग और पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर काम करेगा। महिला अधिकारिता विभाग ने यूएन वुमन के साथ इसके लिए करार भी किया है। *(रा.प., 25.09.16)*

'मां' कार्यक्रम का शुभारंभ

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं शिशु आहार स्तर को सुदृढ़ कर कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से 'मां' कार्यक्रम (मदर्स एब्सल्यूएट एफेक्शन) का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम 29 अगस्त से सभी जिलों में शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में स्तनपान व शिशु आहार के संरक्षण के लिए सामुदायिक स्तर एवं चिकित्सा केन्द्र स्तर पर व्यापक वातावरण विकसित किया जाएगा। स्तनपान के महत्व को बढ़ाने के लिए आशा सहयोगिनों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मिकों के सहयोग से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं व उनके परिजनों सहित जन समुदाय को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। *(दै.न., 23.08.16)*

सड़क सुरक्षा

मोटर वाहन विधेयक समय की जरूरत

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संशोधित मोटर वाहन विधेयक 2016 वर्तमान समय की जरूरत है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार इस विधेयक को संसद में जल्द पारित कराने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सदस्य सांसदों एवं राज्यों के परिवहन मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एवं परिवहन प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए संसद में पेश विधेयक शीघ्र पारित हो, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। विधेयक के पारित होने से देश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के साथ ही सड़क सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

बैठक में सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए गठित राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष राजस्थान परिवहन मंत्री युनूस खान ने बताया कि उन्होंने मंत्री समूह के 18 राज्यों के अलग-अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सुझावों को शामिल कर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें आम आदमी को यातायात नियमों की जटिलता और उनके नाम पर हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए महत्वपूर्ण सुझावों को भी शामिल किया गया है। *(दै.न., 23.09.16)*

वित्तीय सेवाएं

ग्राहक की लापरवाही नहीं तो धोखाधड़ी में जिम्मेदारी बैंक की

इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि बैंक की लापरवाही सामने आई तो ऐसे मामलों में खाताधारक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन ग्राहक ने लापरवाही की है, तो फिर उसका जिम्मेदार भी वह खुद होगा। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ग्राहक की जिम्मेदारी तय करने के लिए लाए जा रहे ग्राहक सुरक्षा प्रस्ताव के मसौदे में रिजर्व बैंक ने यह बात कही है। बैंक ने इस मसौदे पर सभी पक्षों से राय मांगी है।

मसौदे के अहम प्रावधान

- *खाता धारक की लापरवाही स्पष्ट नहीं तो जिम्मेदारी 5000 रु. तक सीमित रहेगी।*
- *ग्राहक को सात कार्य दिवस के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देनी होगी।*
- *सूचना मिलने के बाद बैंक को 10 दिन में पैसे ग्राहक के खाते में डालने होंगे।*
- *बैंक को 90 दिन में समाधान करना होगा, ग्राहक को ब्याज का नुकसान न हो।*

मसौदे में कहा गया है कि बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के मामले में अलर्ट के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने के लिए कहें। बैंक यह अलर्ट एसएमएस और ईमेल जैसे विभिन्न चैनलों से तुरंत भेजे।

ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि गैर इलेक्टॉनिक बैंकिंग ट्रान्जेक्शन में धोखाधड़ी होने पर इस संबंध में तुरंत बैंक को सूचित करे। बैंकों से ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा गया है जिससे ग्राहक सातों दिन चौबीस घंटे बैंक को वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस या टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से सूचित कर सके। *(दै.भा., 12.08.16)*

मानक सेवा

जल्द पास होगा हॉलमार्किंग कानून

देश में जल्द ही सोने-चांदी की ज्वैलरी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य हॉलमार्किंग कानून पास होने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) ने इसे लागू कराने की तैयारियां तेज कर दी है।

देश में दिवाली तक सोने-चांदी की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू की जा सकती है। इसके लिए बीएसआई के पास देश में पर्याप्त सेंटर मौजूद है। पिछले छह महीने के दौरान स्वर्ण उद्योग के लिए कई सुधार लागू करने के बाद अब सरकार सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग पर जोर दे रही है। ग्राहकों के लिए तीन तरीके से हॉलमार्किंग करने का फैसला किया गया है। अब कोड की जगह कैरेट लिखा जा सकेगा।

(रा.प., 08.08.16)

जन स्वास्थ्य

अब हेल्थ चेकअप के लिए एटीएम

अब तक एटीएम मशीन से पैसा निकालते रहे हैं, लेकिन तीन से चार महीनों के अंदर एक ऐसा एटीएम मशीन और मोबाइल टैबलेट आने वाला है जो बीमारी का इलाज करेगा। इस योजना पर स्टार्टअप 'डॉक्टर इंस्टा' काम कर रहे हैं। डॉक्टर इंस्टा दोनों ही तकनीक को भारत में पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गुड़गांव से होनी है। बाद में इसे अन्य जगह लागू किया जाएगा।

पहले चरण में इसकी शुरुआत इनमें एक हेल्थ एटीएम (मिनी लैबोरेटरी) और दूसरा मोबाइल टैबलेट (इंस्टा वाल) है। एटीएम एक बड़ा कियोस्क की तरह होगा जो मॉल्स, कॉरपोरेट पार्क आदि में लगाए जाएंगे। मरीज वहां पहुंचकर अपना इलाज करा सकते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्ट रेट और अन्य सुविधाएं होंगी। इससे जांच और इलाज बेहद सस्ता होगा और गरीबों के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। *(रा.प., 09.09.16)*

दूरसंचार सेवाएं

बिना टेलीफोन कनेक्शन के ब्रॉडबैंड

दुनिया में हर सैकण्ड में 4 इंटरनेट उपभोक्ता नए जुड़ रहे हैं। भारत में भी लगभग यही स्थिति है। राजस्थान का आंकड़ा 2 है। यहां इंटरनेट उपभोक्ता की वृद्धि दर 18 फीसदी है। तेजी से बढ़ते इसी ग्राफ को देखते हुए बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेवा में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड के लिए अब टेलीफोन कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी।

पहली बार टेलीफोन के बिना ब्रॉडबैंड उपलब्ध होगा। इसके लिए ऑप्टीकल फाइबर का ही उपयोग होगा। जयपुर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए काम शुरू हो गया है। फिलहाल बहुमंजिला इमारतों पर खास नजर है। *(रा.प., 14.08.16)*

उपभोक्ता फैसले

रेस्टोरेंट को भारी पड़ा छपी कीमत से ज्यादा पैसा वसूलना

जयपुर स्थित शास्त्री नगर निवासी मनजीत सिंह ने उपभोक्ता मंच-तृतीय में परिवाद पेश कर बताया कि उसने नया खेड़ा, विद्याधर नगर स्थित स्पाइस एन करी रेस्टोरेंट से दो बीयर की बोतल 09 जून, 2011 को खरीदी थी। दोनों बोतल का अधिकतम खुदरा मूल्य 115 रुपए था। जबकि रेस्टोरेंट प्रबन्धन ने उससे 195 रुपए वसूले। जब उसने 80 रुपए ज्यादा वसूलने पर रेस्टोरेंट प्रबन्धन से पूछा तो ठीक से जवाब नहीं दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

मामले की सुनवाई पर मादक पेय पदार्थ पर छपी कीमत से 80 रुपए ज्यादा वसूलने को उपभोक्ता मंच-तृतीय ने गंभीर सेवादोष और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। मंच ने रेस्टोरेंट प्रबंधन पर एक लाख रुपए का दंडात्मक हर्जाना लगाया। मंच ने अपने आदेश में कहा कि एक लाख रुपए के हर्जाने में से परिवादी मनजीत सिंह को 25 हजार रुपए देगा। साथ ही ज्यादा वसूले गए 80 रुपए ब्याज सहित लौटाने होंगे और परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए भी अलग से परिवादी मनजीत सिंह को देने होंगे। जबकि एक लाख रुपए के हर्जाने में से शेष बचे 75 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने होंगे। यह भुगतान एक माह की अवधि में करना होगा।

(डे.न्यू., 12.09.16)

दुर्लभजी अस्पताल पर 10 लाख रुपए का हर्जाना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) ने इलाज में लापरवाही बरतने से महिला की मौत होने पर जयपुर स्थित संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल और डॉ. प्रीति शर्मा पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उपभोक्ता मंच में दुर्लभजी अस्पताल के खिलाफ परिवाद पेश कर मंच को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी आशा के बच्चेदानी में तकलीफ होने पर उसे 22 जून 2005 को दुर्लभजी अस्पतान में भर्ती कराया था। 24 जून को उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में लापरवाही बरतते हुए उसकी बड़ी आंत काट दी, जिसके चलते अपशिष्ट पदार्थ शरीर में फैल गए और उसकी तबियत बिगड़ गई। डॉ. प्रीति शर्मा ने अपनी इस गलती को छिपाने के लिए 25 जून को उनकी पत्नी का वापस ऑपरेशन किया। लेकिन उसमें भी लापरवाही बरती गई जिससे आशा की मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के बाद मंच ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सक को गंभीर लापरवाही का दोषी माना और कहा कि पत्नी की मौत के कारण बच्चे अपनी मां के स्नेह से वंचित हुए हैं और एक पति ने अपनी पत्नी खोई है। मंच ने अस्पताल व डॉ. प्रीति शर्मा पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही परिवाद पेश करने की तारीख से 12 फीसदी ब्याज सहित एक महीने में अदा करने और परिवाद खर्च के 20 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए हैं। *(दै.भा. एवं दै.न., 07.08.16)*

उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उठाए जा रहे हैं कई कदम

उपभोक्ताओं को सशक्त और जागरूक करने के लिए सरकार 'जागो ग्राहक जागो' अभियान समेत कई कदम उठा रही है। उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों को और सख्त बनाने के लिहाज से एक विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 काफी पुराना हो गया है। नए विधेयक में दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों से निपटने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

पासवान ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय हेल्पलाइन भी शुरू कर रही है। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक स्तर पर उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे। पाठ्यक्रमों में भी इस विषय को शामिल करने का विचार है। उपभोक्ता अदालतों के फैसलों को अधिक से अधिक प्रचारित-प्रसारित किया जाए इसके लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई विभाग काम करते हैं और उनके अलग-अलग कानून हैं। इनमें आपसी समन्वय की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी ने बताया कि देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद सभी 36 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे 81 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। *(न.नु., 03.08.16)*

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।